संख्याः 32/2015/1241 /तीस-1-2015-5(18)/2015

प्रेषक,

मुहम्मद अख़लाक़ खॉ,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-1 **लखनऊः दिनाँक 10 सितम्बर, 2015**

विषयः बस स्टेशन एवं डिपो कार्यशाला ललितपुर के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, मुख्यालय लखनऊ के पत्र संख्या-1177बी/15-299ई0ई0(डब्लू)/2012, दिनांक 10-07-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बस स्टेशन एवं डिपो कार्यशाला ललितपुर के निर्माण हेतु उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय द्वारा रू0 476.32 लाख की लागत का प्रारम्भिक आगणन शासन को उपलब्ध कराया गया। उक्त आगणन के सापेक्ष प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड), के पत्र संख्या-5374/क्यू0एफ0/सिविल/टी-408(1) दिनांक 28 अगस्त, 2015 द्वारा रू0 499.72 लाख की लागत का संशोधित आगणन उपलब्ध कराया गया है। अतः प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु रू0 499.72 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी0-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30-03-2015 में निहित निर्देशों के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 249.86 लाख (रूपये दो करोड़ उन्चास लाख छियासी हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तो के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) प्रश्नगत कार्य कराये जाने हेतु उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड), लखनऊ को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है। उ0प्र0 राज्य सडक परिवहन निगम द्वारा उक्त कार्यदायी संस्था से अनुश्रवण करके प्रश्नगत कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

(2) उक्त आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपोजिट खाते में जमा नहीं की जाएगी।

(3) परियोजना का अंतिम रूप में अनुमोदित मानचित्र/डिजाइन के आधार पर विस्तृत आगणन का गठन करते हुए सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) परियोजना निर्माण में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता एवं समयबद्दता अवश्य सुनिश्चित किये जाने का दायित्व उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड), लखनऊ का होगा।

(6) परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

(7) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में स्थल विकास संबंधी जिन कार्यो की लागत डी0एस0आर0 पर प्रस्तावित की गयी हों उन कार्यो का जनपद के शिड्यूल आफ रेट्स पर विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(8) उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड), लखनऊ द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(9) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(10) परियोजना लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों में कोई उल्लेखनीय परिर्वतन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार में वृद्धि, एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राडंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड लखनऊ एवं उ0प्र0 राज्य सडक परिवहन निगम द्वारा 03 माह के अन्दर शासन के माध्यम से समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(11) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से परिवहन निगम द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत हैं और न ही वर्तमान या भविष्य में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(12) प्रश्नगत परियोजनान्तर्गत निर्माण कार्यो को सम्पादित किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था एवं उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा माइलस्टोन्स निर्धारित किया जायेगा और निर्धारित माइलस्टोन्स व तदनुसार कार्यो की प्रगति से समय-समय पर शासन को अवगत कराया जायेगा। निर्माण कार्य को समयबद्धता से पूर्ण कराया जाए साथ ही गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए।

http://shasanadesh.up.nic.in

(13) स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का मासिक विवरण प्रपत्र-बी0एम0-13 में प्रतिमाह वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.03.2015 में दिए गये निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर इस सम्बन्ध में जारी किये गये अन्य निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(14) उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत फर्नीचर, साइन बोर्ड, पंखा, जनरेटर एवं टी0वी रेन वाटर हारवेस्टिंग, इन्टरनल इलेक्ट्रिफिकेशन, इन्टरनल सेनेटरी एण्ड वाटर टयूवेल बोरिंग पाईप लाइन, पम्प हाउस, इक्सटरनल सेनेटरी वर्क, कम्प्यूटर एण्ड टी0वी0 कन्डेटिंग, ओवर हेड टैंक, सरफेस टैंक, वॉशिग प्लेटफार्म, आदि कार्यमदें प्रस्तावित की गयी है, जो प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं, जिन्हें कोटेशन/बाजार दर के आधार पर प्रस्तावित किया गया है। इस संबंध में क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त की जाय। प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यो के शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अंतर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत: निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय। उक्त कार्यमदों पर सेन्टेज चार्ज अनुमन्य नहीं होगा।

(15) उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत मिट्टी भराई हेतु लागत रू0 17.82 लाख प्रस्तावित की गयी है। इस संबंध में दिनांक 08-03-2010 को सम्पन्न बैठक में वित्त व्यय समिति द्वारा दी गयी व्यवस्था के अनुरूप यदि किसी प्रायोजना में मिट्टी भराई की आवश्यकता पड़ती है तो सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय स्तर पर अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया जाय जिसमें सदस्य के रूप में जिलाधिकारी के प्रतिनिधि एवं निर्माण ऐजेन्सी तथा सदस्य-सचिव के रूप में प्रशासकीय विभाग के स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि रहेगे। इस समिति द्वारा अनुमोदित कन्टूर मैप एवं मिट्टी की मात्रा के अनुसार ही प्रायोजना प्रस्तावों/आगणनों में मिट्टी भराई का प्रावधान किया जाय। अन्यथा की स्थिति में मिट्टी भराई मद में प्रस्तावित धनराशि पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। यह प्रक्रिया सन्दर्भित प्रायोजना में नहीं की गयी है। अत: मिट्टी भराई हेतु उक्त के संबंध में उपरोक्तानुसार तकनीकी समिति का अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(16) उक्त व्यय के सम्बन्ध में शासन को उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व परिवहन आयुक्त का होगा। उक्त धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त किया जाएगा।

(17) योजना में अनुमोदित लागत में ही एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कराया जाय। उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को हस्तगत कराने के पश्चात यदि लागत में वृद्धि होती है तो उसे कार्यदायी एजेन्सी अपने श्रोतो से वहन करेगी। शासन द्वारा उक्त बढ़ी हुई धनराशि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्ष 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-03-उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अंश पूंजी विनियोजन-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जाएगा।

3- यह आदेश वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

ह0

(मुहम्मद अख़लाक़ खाँ)

विशेष सचिव।

संख्याः 32/2015 /1241/ (1)/तीस-1-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड), लखनऊ ।
6. वित्त नियन्त्रक, परिवहन आयुक्त, कार्यालय लखनऊ।
7. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
8. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड), लखनऊ ।
9. नियोजन अनुभाग-4 ।
10. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9/परिवहन अनुभाग-3।
11. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन,लखनऊ।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0

(सन्त लाल)

अनु सचिव।

http://srisanadesh.up.nic.in